'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 सितंबर, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 20 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 सितंबर, 2013

एक हजार खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है।

–गौतम बुद्ध

अशिक्षा की ओर बढ़ता देश

डॉ. उदित राज

जो अमरीका एवं यूरोप में हो वह हमारे लिए आदर्श है और अनुकरण करने की पूरी कोशिश की जाती है। अधिकतर उन्हीं नीतियों का अनुकरण करते हैं जो जनविरोधी होता है। ये सारे पूंजीवादी देश होने के बावजूद हमारे तथाकथित सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी सरकार से कई मामलों में वे ज्यादा अच्छे हैं। इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया इसलिए कि वैसा अमेरिका में हुआ। 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा के मौलिक अधिकार (राइट टू एजुकेशन) को लागू किया गया है इस भरोसे के साथ कि सभी शिक्षित होने लगेंगे। सरकारी स्कूलों का निजी एवं सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) तेजी से किया जा रहा है। बजाय कि सरकारी स्कूलों का सुधार किया जाता कि वह निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है। इन नीतियों के क्या परिणाम निकले हैं या होंगे जांच–पड़ताल करना जरूरी है।

जबसे शिक्षा की अनिवार्यता प्राइमरी शिक्षा अर्थात् कक्षा एक से लेकर आठ तक किया गया है, निजीकरण तेजी से बढा है। आरटीई से निजीकरण को बढावा मिला है तो यह कहना, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2012 को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षित करना होगा। ज्ञात रहे कि इनकी फीस सरकार भुगतान करेगी। जिन निजी स्कूलों की कमाई भारी–भरकम पहले से ही है, उनके ऊपर प्रभाव तो उतना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इस सरकारी 25 प्रतिशत फीस पाने की लालच में तमाम बहुत ही न्यूनतम स्तर के स्कूल धड़ाधड़ खुल रहे हैं। अच्छे निजी स्कूलों में मध्यम वर्ग के अभिभावक भी इस श्रेणी में अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूल दिन प्रति दिन कमजोर होते जा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां निजी क्षेत्र के सहयोग से शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हुआ हो तो कैसे हम भारत में ऐसा होना संभव मान सकते हैं? इस कानून के आने के बाद सरकार का ध्यान सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का लगभग खत्म सा ही हो चुका है। इस कानून में सबसे बड़ी कमी यह भी है कि यह शिक्षा का सर्वव्यापीकरण कक्षा आठ तक के लिए है जबकि यूरोप एवं अमेरिका में कक्षा 12 तक है।

जर्मनी एक शुद्ध पूंजीवादी देश है लेकिन वहां पर न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि पीएचडी तक छात्रों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। वहां पर निजी स्कूल की बात कही जाए तो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। फ्रांस में भी शिक्षा मुफ्त है सबसे ज्यादा तरक्की शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड ने किया है। 30 साल के अंदर जो भी शिक्षा निजी क्षेत्र में थी, प्राइमरी शिक्षा से लेकर पीएचडी तक का सरकारीकरण कर दिया गया। हमारे यहां इसके विपरीत मुहिम चल रही है कि जो भी तरीके अपनाना हो, शिक्षा का व्यापारीकरण एवं निजीकरण किया जाए। गत् 20 वर्षो से इरादतन सरकारी स्कूलों की शिक्षा को खराब किया जा रहा है और कई बड़े–बड़े उदाहरण मिल जाएंगे जिससे आसानी से पुष्टि हो जाएगी कि गरीबों, ग्रामीणों, दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। दिल्ली नगर–निगम ने कुछ स्कूल स्वंयसेवी संस्थाओं को सौंपा और परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का स्तर गिर गया और बच्चों के ऊपर वित्तीय भार बढा दिया गया। एक एनजीओ लोक शिक्षक मंच ने इस पर विस्तार में रिपोर्ट तैयार करके सिद्ध कर दिया है।

शिक्षा का निजीकरण जितना तेज होगा उतना ही आम जनता के पहुंच के बाहर होगी। कर्नाटक सरकार ने 12000 स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। राइट टू एजूकेशन के बाद सरकारी स्कूल एवं शिक्षण संस्थान तेजी से बंद हुए हैं। कर्नाटक में इससे पहले 3000 ही बंद हुए थे लेकिन अब यह आंकड़ा 12000 तक जा पहुंचा है। आंध्रप्रदेश में पहले 6000 स्कुल बंद हुए थे और अब 1165 किए गए। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसी वर्ष 1174 स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया गया है और उत्तराखंड में 2200 स्कूल। अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति अब इस व्यवसाय में लग गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसका कंपनीकरण कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। रिलायंस एवं अजीम प्रेमजी जैसे लोग सार्वजनिक और निजी साझेदारी में शिक्षण संस्थाओं को लेंगे तो मुनाफा नहीं कमाएंगे। जो अनुसूचित जाति के बच्चे प्रवेश लेते हैं, कक्षा 12 तक पहुंचते–पहुंचते 92 प्रतिशत पढाई छोड़ देते हैं, जनजाति के 94 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 91 प्रतिशत, पिछड़े 90 प्रतिशत। जो ज्यादा पैसा देगा उसको ज्यादा शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी में मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि इन स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाने के बजाय प्रयास करेंगे कि कब इनका निजीकरण हो और वह खरीद लें ताकि कीमती बिल्डिंग और जमीन हड़प लिए जाएं। इस समझौते में शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी कोई प्रावधान नहीं है और यह भी अधिकार दिया गया है कि इनके स्थान पर अपने शिक्षक रख सकते हैं। जब से राइट टू एजुकेशन आया है सरकार लगभग 5000 करोड़ रूपय सालाना फीस के रूप में निजी स्कूलों को भुगतान कर रही है। आंध्रप्रदेश में लगभग 785 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और वर्ष में लगभग 4500 करोड़ रूपए इन इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एमबीए, एमसीए एवं मेडिकल संस्थाओं को सरकार फीस के रूप में भुगतान कर रही है। यह प्रदेश के बजट का चार प्रतिशत है। कुल शिक्षा का बजट 10,000 करोड़ रूपया है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह सरकारी खजाने की लूट हो रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही पूरे देश में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू किया है। ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन की ओर से भारी विरोध करने के बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगी। 1992 में देश की शिक्षा नीति संसद के अनुमति से बनी थी जिसमें 10+2+3 था और कैसे ये कुलपति स्वयं के फैसले से इसे बदलकर 10+2+4 कर सकता है। भारी विरोध के बाद भी कुलपति को हटाया नहीं गया क्योंकि मानव संसाधन मंत्रियों का जबरदस्त समर्थन था। परिणाम आने लगे हैं कि दलित, आदिवासी एवं पिछड़े छात्र पढाई छोड़कर के भागेंगे या दो वर्ष पर डिप्लोमा लेंगे या तीन वर्ष पर डिग्री लेकिन बहुत ही कम होंगे जो चार वर्ष पूरा कर सकेंगे। फाउंडेशन कोर्स में भी कला के छात्र विज्ञान, अंग्रेजी और गणित पढने के लिए मजबूर हो गए हैं और ऐसी स्थिति में पढाई छोड़ने वालों की रफ्तार और बढ जाएगी। तीन साल के जगह पर चार साल पढाई का भार लंबा है और इससे वित्तीय भार भी बढेगा। भारतीय भाषाओं को पढने वाले छात्रों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो गई है। चारों तरफ घोर आलोचना हो रही है फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हाल ही में एफवाययूपी पर लेडिज श्रीराम कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसमें एमी बी. एम. सूई, चेयरमैन, स्टीयरिंग कमिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी और जेन ओलमेयर वॉयस प्रोवोस्ट, त्रिनिटी कॉलेज, डबलिन ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में यह कोर्स लागू किया जा रहा है,

शेष पृष्ठ 2 पर...

सामाजिक न्याय की लड़ाई का बदलता स्वरूप

एचएल दुसाध

वर्ण व्यवस्था में शक्ति के सारे स्त्रोत चिरस्थाई तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से युक्त सवर्णों के लिए आरक्षित रहे, जबकि शुद्रातिशूद्र कही जाने वाली बहुसंख्यक आबादी इनसे पूरी तरह वंचित रही। फिर शक्तिसंपन्न तीन उच्च वर्णों की सेवा का भार भी उस पर थोप दिया गया, वह भी पारिश्रामिक रहित। अगर मार्क्स के अनुसार, दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है तो भारत में वह संघर्ष वर्ण-व्यवस्था के संपन्न तथा वंचित वर्गों के मध्य होता रहा है।

आधुनिक भारत के निर्माताओं ने वंचित बहुसंख्यकों को शक्ति के स्रोतों में उनका प्राप्य दिलाने के लिए एक नई मानवतावादी आरक्षण जैसी व्यवस्था को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर शक्तिसंपन्न तथा वंचित समूहों के बीच लगातार, कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से संघर्ष चलता रहा है। यह संघर्ष प्रायः इकतरफा, शक्तिसंपन्न तबकों की तरफ से होता रहा है। गुलाम भारत में जब पूना-पैक्ट के रास्ते अछूतों को आरक्षण मिला, तब उसके प्रमुख शिल्पी भारत रत्न आंबेडकर को क्या-क्या कहकर गाली नहीं दी गई।

बहरहाल, शक्तिसंपन्न तबकों ने धीरे-धीरे दलित, आदिवासियों को मिले आरक्षण को झेलने की तो मानसिकता विकसित कर ली, किन्तु जब मंडल की सिफारिशों पर 1990 में पिछड़ों को आरक्षण मिला तो शक्तिसंपन्न तबके के युवाओं ने आत्मदाह से लेकर राष्ट्रीय संपत्ति की दाह तक का सिलसिला शुरू कर दिया। एक पार्टी विशेष ने राम जन्मभूमि मुक्ति के नाम पर आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन ही खड़ा कर दिया, जिसके फलस्वरूप बेशुमार संपदा नष्ट हुई और अनेक लोगों की मौत हुई। बाद में, 2006 में जब पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण मिला तो शक्तिसंपन्न समुदाय के युवाओं ने एक बाार फिर गृह-युद्ध की स्थिति पैदा कर दी।

इस बार जुलाई-अगस्त में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नई आरक्षण नीति लागू करने को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ उसकी पहलकदमी भी शक्तिसंपन्न तबके के छात्रों ने ही की। 11 जुलाई, 2013 को यूपी राज्य लोक सेवा आयोग से नई आरक्षण व्यवस्था लागू करते हुए प्राथमिक से लेकर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार तीनों में आरक्षण और ओवरलैपिंग कर कटऑफ सूची जारी की गई, जिससे सफल उम्मीदवारों में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत 76 हो गया। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों ने इस मामले का यह कहकर विरोध करना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए। उन्होंने आयोग के निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायायलय में याचिका दायर कर दी, जिस पर कोर्ट ने 15 जुलाई को आयोग तथा राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा, किन्तु आरक्षण विरोधी छात्र यहीं नहीं रूके। उन्होंने दबाव बनाने के लिए मंडल-1 और 2 की भांति तोड़-फोड़ तो शुरू की ही, किन्तु इस बार उनके हमले का नया पहलू यह रहा कि उन्होंने एक जाति विशेष से जुड़े पेशे, पशुओं और भगवान तक को निशाना बना डाला।

जब पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव सवर्णों के पक्ष में जा खड़े हुए

एक ओर जहां आरक्षण विरोधियों का तांडव जारी था, वहीं दूसरी ओर उनके कुछ सदस्यों ने सपा की एक नेत्री (डॉ. रंजना वाजपेयी) के नेतृत्व में सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। मुलायम उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सके। मुलायम के इशारे के बाद उस दिन देर शाम तक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। आयोग ने नई आरक्षण नीति वापस लेकर आरक्षण विरोधियों को जश्न में डूबने का अवसर दे दिया।

आरक्षण पर आयोग द्वारा यू टर्न लेते ही जहां एक ओर आरक्षण विरोधी जश्न में डूबे वहीं, आरक्षण समर्थकों का आक्रोश भी फट पड़ा। आरक्षण समर्थकों का गुस्सा राज्य की सत्तासीन सपा सरकार पर फूटा। उन्होंने शुरू में सपा के जिलाध्यक्ष के घर धावा बोला और फिर पथराव व वाहनों की तोड़-फोड़ की। उनके एक गुट ने 27 मई को उस सवर्ण सपा नेत्री के घर पर भी धावा बोला तथा पथराव किया, जिनके नेतृत्व में आरक्षण विरोधियों के सपा मुखिया से मुलाकात के बाद सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया था। बाद में उन्होंने इलाहाबाद स्थित सपा के जिला कार्यालय पर कब्जा जमा लिया। वहां दो दिन रहने के बाद उन्होंने 30 जुलाई को लखनऊ घेरने की घोषणा कर दी। उनके उस घोषणा के बाद एक अखबार में छपी टिप्पणी ने मुझे आरक्षण समर्थकों को करीब से देखने के लिए बाध्य किया। 30 जुलाई को उस अखबार में लिखा- 'आरक्षण समर्थकों के निशाने पर सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव तो हैं ही, मायावती भी नहीं बच पाई हैं। किन्तु सबसे खास बात यह है कि आरक्षण समर्थक बसपा संस्थापक कांशीराम को दलितों और पिछड़ों का मसीहा बता रहे थे। वे कह रहे थे कि कांशीराम ने जो लड़ाई शुरू की उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी जाएगी। हालांकि मैंने फेसबुक पर भी कुछ ऐसी बातें देखी थीं, पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिछड़े वर्ग के हिरावल दस्ते के युवाओं के हाथ में आंदोलन का नेतृत्व है, वे कांशीराम को अपना मसीहा मानेंगे। ऐसे में, मैं 30 जुलाई को लखनऊ विधानसभा के विपरीत अवस्थित धरनास्थल पर पहुंचा और वहां जो कुछ देखा, उससे लगा अखबार की सूचना गलत नहीं थी। धरनास्थल पर आरक्षण समर्थक छात्रों ने जो ढेरों बैनर-पोस्टर लगा रखे थे उनमें कई पर लिखा था - 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी।' यही नहीं डेढ घंटे रहने के दौरान छोटे-बड़े कई सामाजिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों के लोगों एवं छात्रों के माहौल को उतप्त करनेवाला आक्रामक भाषण सुना। वे कल्पनातीत निर्ममता के साथ सपा और बसपा प्रमुखों की आलोचना कर रहे थे, परंतु सभी वर्तमान आंदोलन के एजेंडे महज नौकरियों तक सीमित न रखकर, हर क्षेत्र में ही कांशीराम का भागीदर्शन दर्शन, जिसकी जितनी संख्या भारी... लागू करवाने तक प्रसारित करने का आह्वान कर रहे थे और श्रोता छात्र तालियां बजाकर उनका समर्थन कर रहे थे। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाए जाने तक नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। लेकिन सारांश में अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि आरक्षण समर्थकों का यह आंदोलन सामाजिक न्याय के आंदोलनों के इतिहास का एक नया आगाज है। यदि इससे जुड़े छात्र इसी संकल्प के साथ कांशीराम की भागीदारी दर्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ सामाजिक न्याय का अध्याय पूरा हो सकता है, बल्कि भारत में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

(साभार- फारवर्ड प्रेस)

शेष पृष्ठ 1 का...

वह बेहद अनुचित है। हांगकांग यूनिवर्सिटी में इसे लागू करने के लिए 7 साल तक प्रयोग चलता रहा। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में इसे आनन-फानन में लागू किया गया और तीन वर्ष का पाठ्क्रम समाप्त हो गया। त्रिनिटी कॉलेज, डबलिन में तीन वर्ष के पाठ्यक्रम को खत्म नहीं किया बल्कि साथ-साथ चलाये रखा।

देश की शिक्षा नीति बद से बदतर होती जा रही है। ग्यारहवीं और बारहवीं योजना में पर्याप्त पैसा मिला लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय उसका प्रबंधन नहीं कर सका। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भारी पैसों की लूट हुई है। यूरोप और अमेरिका की नीतियों को सरकार आंख मुंदकर के नकल करती है उनसे यह भी सीखना चाहिए कि वहां पर स्नातक स्तर पर भारी संख्या में छात्रवृत्ति है जबकि हमारे यहां थोड़ा बहुत है भी तो शोध स्तर पर। गरीब बच्चें जब स्नातक ही नहीं कर पाएंगे तो उच्च शिक्षा में कैसे पहुंच सकेंगे? अब एक मुहिम और तेज हुई है कि फारेन एजुकेशन प्रोवाइडर को यहां पर अपने कैम्पस खोलने की इजाजत दिया जाए। क्या विदेशी शिक्षण संस्थाएं यहां पर धर्माधा का काम करने आ रही है सिवाय पैसा कमाने का? पीपीपी, आरटीई, एफवायययूपी एवं अन्य शिक्षा नीतियां आम जनता को समान शिक्षा से वंचित कर रही हैं और उच्च शिक्षा बहुत ही कम लोगों के लिए संभव हो पाएगी। अमेरिका से हटकर हमारे यहां उच्च शिक्षा मान-सम्मान, भागीदारी, शासन-प्रशासन से जुड़ी हुई है। इससे वंचित करने का मतलब साफ है कि इसका सबसे ज्यादा असर दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों पर पड़ेगा।

परिनिर्वाण भूमि समिति की वायएमसीए भवन में बैठक संपन्न

डॉ0 अम्बेडकर की उपेक्षा करना केन्द्र सरकार को महंगा पड़ेगा, चार राज्यों के रेलवे ट्रैक को जाम करके होगा दलित आंदोलन

टी. एम. कुमार

नई दिल्ली। डॉ0 अम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति की बैठक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री इन्द्रेश गजभिये की अध्यक्षता में नई दिल्ली के वाय. एम.सी.ए. भवन, जयसिंह रोड पर सम्पन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख दलित नेता – डॉ0 सत्य नारायण जटीया – पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डॉ0 उदित राज – राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/ जन जाति परिसंघ, श्री सुनील रामटेके – राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी, श्री इंदर सिंह अटवाल – अकाली दल, श्रीमती मायाताई चवरे – समाजवादी पार्टी, श्री अनिल सैनी – बहुजन समाज पार्टी सहित अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश कमेटी के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में सम्मिलित हुये। बैठक का संचालन राष्ट्रीय संयोजक, श्री टी.एम. कुमार ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री इन्द्रेश गजभिये, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधान सभा के सामने डॉ0 अम्बेडकर की निधन स्थली है, जिसे 2003 में एन.डी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके इस निर्माण की सौ करोड़ की कार्ययोजना बनाई थी, किंतु केन्द्र की मौजूदा यूपीए सरकार पिछले दस वर्षों से इसकी लगातार उपेक्षा की है। इसे गांधी समाधि राजघाट के बराबर दर्जा नहीं दिया गया। इसके आस-पास के बंगलों का अधिग्रहण नहीं किया गया, जिससे देश का दलित समाज यूपीए सरकार से नाराज है। इसलिए नवंबर माह में चार राज्यों – पंजाब, उ0प्र0, म0 प्र0 एवं महाराष्ट्र में रेल रोककर ट्रैक जाम किया जाएगा, जो आगामी चुनाव में यूपीए को महंगा पड़ेगा।

डॉ0 सत्य नारायण जटीया ने कहा कि जब वे भारत के सामाजिक न्याय मंत्री थे तब उन्होंने इस स्थान को खरीदकर सम्मान देने का काम किया था। केन्द्र सरकार ने गांधी जी को राष्ट्रपिता मानकर राजघाट को उच्च सम्मान दिया है तो उसे डॉ0 अम्बेडकर जी को संविधान पिता मानकर वैसा ही सम्मान परिनिर्वाण भूमि को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूना पैक्ट करके जिसने दलितों के अधिकारों को छीना है, उसे देश के दलित राष्ट्रपिता कैसे स्वीकार कर सकते है?

डॉ0 उदित राज ने कहा कि प्रधानमंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह पर हमने 4 अक्टूबर, 2011 को भरोसा करके नागपुर का रेल रोको आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन उन्होंने जो उच्च स्तरीय कमेटी डॉ0 नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में बनाई, उसमें उन्होंने आंदोलन समिति के लोगों को नहीं रखा और अपने मन पसंद लोगों की कमेटी से उन्होंने दलित विरोधी रिपोर्ट में हस्ताक्षर करा लिये, जिससे डॉ0 अम्बेडकर को पूरा सम्मान नहीं देने की केन्द्र सरकार की मंशा उजागर हुई है।

बैठक को श्री किरणजीत सिंह गेरी, श्री परमजीत सिंह केंथ (पंजाब),श्री अनिल खोब्रागड़े, श्री अनिल गजभिये (छत्तीसगढ़), श्रीमती माया चवरे, श्री बाबूराव नरवड़े (महाराष्ट्र), श्री जेगेश्वर गर्ग, श्री चुन्नीलाल रतवाया (राजस्थान), श्री भवननाथ पासवान, श्री शांत प्रकाश, श्री राजकिशोर वर्मा (उ0प्र0), श्री सुरेन्द्र भगत, श्री संतोष राज नेगी (जम्मू एवं कश्मीर), श्री डी.एस. विरैया (कर्नाटका), श्री जी.रंगनाथन (तमिलनाडु), श्री राधाकिशन बकोरिया, श्री प्रकाश वर्मा, श्री संदीप भोरजार, सुश्री क्रांति चौधरी (म0प्र0),श्री कैलाश सांखला,श्री अशोक कुमार (दिल्ली), श्री सूरजभान कटारिया, श्री नंदलाल धानिया (हरियाणा), श्री जयंती भाई परमार, श्रीमती ज्योति बागला (गुजरात), श्री रमेन्द्र प्रसाद, श्री अनिल कुमार (बिहार) आदि ने सम्बोधित किया।

22 सितंबर, 2013 को मध्यप्रदेश परिसंघ एवं नसोसवायएफ का संयुक्त प्रदेश सम्मेलन

मध्यप्रदेश परिसंघ एवं नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) का संयुक्त प्रदेश सम्मेलन भोपाल के गांधी भवन, पॉलिटेक्निक चौराहा में आगामी 22 सितंबर, 2013 को रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ. उदित राज होंगे। यह आयोजन वरिष्ठ आईएएस डॉ शशि कर्णावत, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आप सभी परिसंघ के पदाधिकारियों, छात्रों एवं नौजवानों से आग्रह है कि सम्मेलन में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाएं।

निवेदक

श्री परमहंस प्रसाद

प्रदेश अध्यक्ष, परिसंघ, मध्यप्रदेश

मो.-09424746393

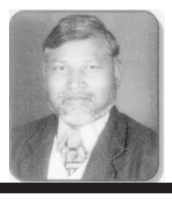

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

परिसंघ का प्रांतीय सम्मेलन

भवननाथ पासवान

लखनऊ। गत् दिनों 25 अगस्त को अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का उत्तर प्रदेश का सम्मलेन संपन्न हुआ। परिसंघ के प्रांतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज (राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ) व सम्मेलन की अध्यक्षता परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भवननाथ पासवान, विशिष्ट अतिथि कौशल किशोर (पूर्व राज्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पारख महासंघ), पी. सी. कुरील (राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन), एहसानुल हक मलिक (राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा समाज महासंघ), राम विरज रावत (अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सचिवालय एससी/एसटी/अधिकारी/कर्मचारी कल्याण समिति) उपस्थित थे। सम्मेलन का संचालन परिसंघ के जिला अध्यक्ष रामसजीवन ने किया।

सम्मेलन में परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भवननाथ पासवान ने सभी मंडल, जिलों से आये पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 नवंबर 2013 को रामलीला मैदान, दिल्ली में होने वाली रैली में प्रत्येक जिले को 10 हजार साथियों को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में परिसंघ के साथी सम्मिलित होंगे। पासवान ने कहा कि परिसंघ के जिला अध्यक्ष आज से रैली की तैयारी में लग जायें। अपने जिलों में पहुंचने के बाद जिला सम्मेलन बुलायें। संगठन को सक्रिय करने के लिए सदस्यता अभियान चलाये। जिला अध्यक्ष जहां कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। 25 नवंबर की रैली से पहले कार्यकारिणी का गठन करके एक सूची प्रदेश कार्यालय को भेजे।

श्री पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित अधिकारी कर्मचारियों को महत्वहीन पदों में नियुक्ति की जा रही है और तरह-तरह से उनका उत्पीड़न, शोषण किया जा रहा है। परिसंघ अब उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु धरना-प्रदर्शन आदि करके उनकी समस्याओं का निराकरण करायेगा।

एससी/एसटी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण जिंदगी और मौत का सवाल है। इसे पूरी ताकत से हासिल करना चाहिए। इससे करोड़ो दलितों को लाभ मिलेगा।

श्री राज ने कहा कि इस देश में जब तक सामाजिक संगठनों द्वारा समाज को जागरूक नहीं किया जायेगा तब तक दलित समाज का भला नहीं होने वाला। राजनीति में कुछ लोगों का भला हो सकता है। जैसे देश की संसद में 121 सदस्य तथा प्रदेशों की विधानसभाओं से 945 लगभग विधायक होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार का ही भला कर सकते हैं लेकिन समाज को कुछ नहीं मिल सकता है।

इसलिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना है। निजीकरण बढ रहा है जिससे धीरे-धीरे आरक्षण समाप्त हो रहा है दलित समाज को सचेत होने की आवश्यकता है।

श्री राज ने बोलते हुए कहा कि 28 जुलाई से दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में बनी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है। छात्र नेता एवं आरक्षण समर्थक विनोद यादव, अजीत यादव, लाला राम सरोज, सुरेंद्र चौधरी, आर. के. गौतम, आदि की अगुवाई में यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया है। 30 जुलाई को जब अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर

मंच पर (दांये से) अनिल कुमार, पी. सी. कुरील., डॉ. उदित राज, भवननाथ पासवान, कौशल किशोर एवं अन्य को माला पहनाकर स्वागत करते लोग।

लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे तो इन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा गया। डॉ. उदित राज ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय की बुनियाद पर बनी है तो क्या यही सामाजिक न्याय है कि जब अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोग स्वाभाविक अधिकार की मांग करें तो उनको बर्बरता से पीटा जाए। इनकी मांग है कि प्रारंभिक एवं मुख्य शिक्षा के स्तर पर ही पिछड़ों एवं दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए न कि साक्षात्कार के समय। परिसंघ ने संकल्प लिया है कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का हर कदम पर सहयोग किया जाएगा। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों को दिया गया है न कि सवर्णो को लेकिन जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है वह सवर्ण को ही आरक्षित श्रेणी में रखती है। इसके अनुसार सवर्ण का आरक्षण 50 प्रतिशत सरकारी सेवाओं में हो जाता है।

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण न होने से पहले ही अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रतियोगी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। भले ही बाद में आरक्षण का प्रावधान हो फिर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। भले ही यह अफवाह हो कि आरक्षण वाली सरकारी नौकरियां खा ले रहे हैं, यह मिथ्या है। आज भी लगभग 70 प्रतिशत से अधिक उच्च पदों पर सवर्ण ही है। पिछड़ों का आरक्षण तो पूरा ही नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायपालिका भी आरक्षण विरोधी है। 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी आरक्षण विरोधी रवैया अपनाया। श्री मुलायम सिंह जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भावनावश पिछड़ों का वोट पक्का है और आरक्षण विरोधी रवैये से सवर्ण खुश हो जाएंगे और इन हालातों में उनके कुनबे का भला होता रहेगा न कि पिछड़ों का। जो लोग यह चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि आरक्षण से सवर्णो के अवसर कम हो गए हैं तो केंद्र सरकार में उच्च पदों पर आसीन सवर्णो की भागीदारी से पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। 1 जनवरी, 2011 के अनुसार, कुल 149 सचिव में से अनुसूचित जाति के लोगों की उपलब्धता शून्य थी तो वहीं जनजाति के मात्र 4 लोग थे। 108 एडिशनल सेक्रेटरी में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में ही लोगों की संख्या मात्र 2 थी। ज्वाइंट सेक्रेटरी के 477 पदों पर अनुसूचित जाति से मात्र 31 तो जनजाति से 15 लोग ही थे। वहीं 590 निदेशकों में अनुसूचित जाति के 17 तो जनजाति के मात्र 7 लोग निदेशक पद पर थे। पिछड़े वर्ग की स्थिति तो और भी खराब है।

सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रदेश पदाधिकारी परिसंघ डॉ. अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, डॉ. बलराम, महावीर सिंह, राम सिंह, रघुनंदन प्रसार, आर. डी. प्रेमी, ई. रामरतन, बी. पी. वर्मा, पंचम लाल, वी. एल. सोनकर, महेंद्र कुमार गौतम, श्रीमती रीना रजक (परिसंघ प्रदेश अध्यक्ष, महिला) तथा मंडल पदाधिकारियों में जी. डी. सोनकर, राकेश बहादुर, शैलेंद्र कुमार भारती, योगेंद्र कुमार, राधेश्याम राय (जिला अध्यक्ष, लखनऊ), राम सजीवन, बालक राम गौतम आदि।

सफाई कामगारों का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 अक्टूबर को दिल्ली में

स्थान : डिप्टी चेयरमैन हॉल, कॉन्सटीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ की ओर से 5 अक्टूबर को डिप्टी चेयरमैन हॉल, कॉन्सटीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। विचार किया जाएगा कि जन्म के आधार पर यही जाति क्यों दूसरों का मलमूत्र साफ करने और ढोने का काम करती है? देश में विभिन्न लोग एवं संगठन इनके उद्धार के लिए सक्रिय तो हैं फिर भी इनकी स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। भारत की संसद में 7 सितंबर, 2013 को मुविंग द प्रोहिबिशन ऑफ एम्पलॉयमेंट ऐज मैन्युल स्कैवेंजर्स एंड देअर रिहैबिलिटेशन बिल पास हुआ। क्या इससे भी इस मानसिक दासता से मुक्ति मिल पाएगी? सफाई कर्मचारियों की जितनी खराब जिंदगी है शायद दुनिया में किसी भी जाति और कौम की नहीं होगीं। जब से ठेकेदारी की प्रथा लागू हुई है तब से आर्थिक शोषण और तेज हो गया है। अर्थात् पहले तो मानसिक शोषण ज्यादा था लेकिन अब दोनों ही भयंकर रूप से हो गए हैं। इस सम्मेलन में भाग लेकर के इस दासता को खत्म करने में सहयोग दें।

विनोद कुमार
राष्ट्रीय चेयरमैन
मो.-9871237186

अब होगा देशव्यापी आन्दोलन

शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

सी. एल. मौर्य

नई दिल्ली, 8 सितंबर। ज्वाइंट ऐक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन (एससी/एसटी/ओबीसी/लेफ्ट) की ओर से स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देश के कोने-कोने से बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री, शिक्षाविद् विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता, नौजवान एवं छात्र नेता इसमें शामिल हुए। आज के सम्मेलन में तय किया गया कि एफवाईयूपी एवं शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा।

डॉ0 उदित राज, संयोजक, ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन (एस.सी./एस.टी./ओबीसी.) (जाफ्डे) की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) के विरुद्ध हुआ था। इस शिक्षा नीति से दलित, आदिवासी, पिछड़े, ग्रामीण एवं भारतीय भाषाओं के विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जाफ्डे की शुरुआत मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम दलित, पिछड़े एवं वामपंथी संगठनों से हुई थी, उसके बाद इसका स्वरूप बड़ा होता गया।

शिक्षा मंत्री श्री पल्लम राजू एवं श्री शशि थरूर को अब तो होश आना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लागू किए गए एफवाईयूपी का गलत समर्थन किया। हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें डीटीएफ नेता, प्रो0 नंदिता नारायण की जीत अध्यक्ष पद पर हुई। यह चुनाव वर्तमान शिक्षा नीति पर जनमत संग्रह की तरह हुआ है। छात्रों द्वारा भी जनमत संग्रह कराया गया और नतीजा यह हुआ कि 11,556 वोटों में से 91 प्रतिशत एफवाईयूपी के खिलाफ हुआ। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि सरकार अविलंब एफवाईयूपी को समाप्त करे और विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त।

सम्मेलन के दौरान मंच पर (दांये से) डॉ. उदित राज, डॉ. हनी बाबू, डॉ. एस. के. सागर, नंदिता नारायण, विनोद कुमार एवं अन्य।

ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन का मूल उद्देश्य शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण को रोकना है। शिक्षा का निजीकरण इस कदर बढ़ रहा है कि कुछ दृष्टांतों से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने 12,000 स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। राइट टु एजुकेशन के बाद सरकारी स्कूल एवं शिक्षण संस्थान और तेजी से बंद हुए हैं। कर्नाटक में इससे पहले 3000 ही बंद किए गए थे लेकिन अब 12000। आंध्र प्रदेश में पहले 6000 बंद किए गए थे और अब 1165 किए गए हैं। बंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में इसी वर्ष में 1174 स्कूल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया गया है। उत्तराखंड में 2200 स्कूल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षा का कंपनीकरण। अनुसूचित जन जाति के बच्चे कक्षा 12 तक जाते-जाते 94 प्रतिशत पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति के 92 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 91 प्रतिशत, पिछड़े 90 प्रतिशत छात्र कक्षा 12 तक स्कूल जाना बंद कर देते हैं।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि माह अक्टूबर में हजारों लोगों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव तब तक किया जाएगा, जब तक एफवाईयूपी वापिस नहीं होता। दलित सांसदों को विशेष रूप से सम्पर्क किया जाएगा कि वे एफवाईयूपी को वापिस कराने का मुद्दा संसद में उठाएं। उपरोक्त मुद्दों पर आगामी 25 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय रैली आयोजित की जाएगी।

सम्मेलन को डॉ0 उदित राज के अलावा डूटा अध्यक्ष, नंदिता नारायण, प्रो0 हैनी बाबू, प्रो0 शास्वती मजूमदार, डॉ0 बलराज, डॉ0 प्रेम सिंह, डॉ0 सदाशिव आदि ने मुख्य रूप से सम्बोधित किया।

नसोसवायएफ की राष्ट्रीय चिंतन बैठक संपन्न

लाखों की तादाद में 25 नवंबर को दिल्ली में इकट्ठा होगें छात्र एवं युवा

हर्षवर्धन दवणे

गत् दिनों 9 सितंबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड युथ फ्रंट (नसोसवायएफ) की राष्ट्रीय चिंतन बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य मार्गदर्शक डॉ. उदित राज थे। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए छात्र एवं युवा नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसमें विभिन्न राज्यों में संगठन की कार्यप्रणाली के ऊपर चर्चा हुई। डॉ. उदित राज ने इस बैठक में मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नसोसवायएफ देश का पहला ऐसा छात्र एवं युवा संगठन है जो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है और निजी क्षेत्र में आरक्षण से ही देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी को शिक्षा, रोजगार, उद्योग, फिल्म, पत्रकारिता, खेल एवं अन्य क्षेत्र में भागीदारी तय होगी। आज यह भागीदारी न के बराबर है इसलिए नसोसवायएफ को एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय जनआंदोलन खड़ा करने की जरूरत है।

इस चिंतन बैठक में डी. हर्षवर्धन (नेशनल कोऑर्डिनेटर) ने आगामी 25 नवंबर को लाखों की भीड़ दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा करने के लिए अभी से विभिन्न राज्यों के छात्र नेताओं के प्रचार-प्रसार करने का विचार रखा। डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में छात्र और युवा निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ी क्रांति कर सकते हैं। डॉ. उदित राज समाज के आज और कल के लिए लड़नेवाले एकमात्र सच्चे अंबेडकरवादी नेता हैं। इनके नेतृत्व में हम छात्र एवं युवा अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। इस चिंतन बैठक में दिनेश अहिरवार (जेएनयू) ने कहा कि आज समाज जिस स्थिति में जी रहा है उससे अगर बेहतर स्थिति में आना है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा करना हमारी जरूरत है। इस बैठक में महाराष्ट्र से भावना इलपाची, नितिन गायकवाड, के. बालाजीराव, रवि सुर्यवंशी, गणेश वाघमारे, अतुल आम्टे, विनोद मसदे, मध्यप्रदेश से सुशील बरखने, प्रताप सिंह अहिरवार, दिल्ली से योगश कृष्णा, मुकेश अहिरवार, बलवीर, उत्तर प्रदेश से सोनू सुयर्ववंशी एवं बिहार, हरियाणा से छात्र एवं युवा नेता इस राष्ट्रीय चिंतन बैठक में उपस्थित हुए।

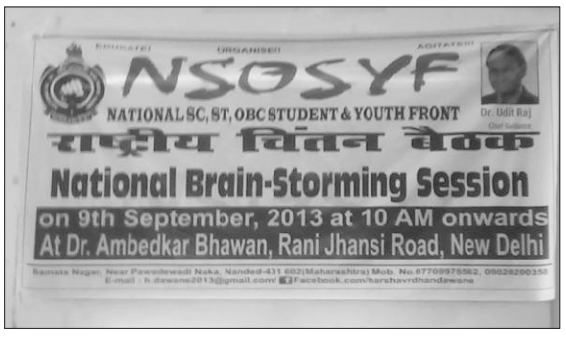

Three years of RTE act:

TIME TO INTROSPECT

This year marks one more milestone in the struggle for free and compulsory education in India. March 31, 2013 was the deadline for the implementation of Right to Education act, 2009 across the nation. The journey has not been an easy one, mixed with success and faliure; it has been demanding readical shifts at various levels of our education system. Reports abound in the media pertaining to the failures in meeting many RTE norms. There is still a shortage of 12 lakh teachers in primary schools, 20 % teacheres employed are untrained and the student teachers ratio falls short of the prescribed norms. News agencies have also been reporting about the practical difficulties in its execution espesically faced by the poor.

ASER's latest report on the deteriorating learning levels in schools interestingly raises concerns over certain RTE norms. It states that "Learning levels started dropping in many states since RTE came into effect. Coincidence? Correlation? Or, causation?" The report reflects a general feeling that RTE may have led tothe relaxation of classroom teaching with scraping of all exams and assessments. Without a working alternative mechanism like CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) the problems have increased many folds. It also signals the weakening public eduacation system in the country and predicts that more than 50% of the children in India will pay for their primary education by 2020.

In addition tdo the above isssues 25% reservation quota for poor in private schools has created a lot of hue and cry. In its present form it is showing more discriminatory practices and cultural gaps. In urban Bangalore there was a report about poor and schedule caste kids cleaning toilets and kitchens in a school. Isn't this outrageous? But our 21st century educated teaches and parents feel fine with this, considering it a normal practice. In such a condition, can the mixing of poor and rich children work in this society? In a society so deeply rooted with discriminations based on caste, creed and socio-economic status, is it possible that our dreams for social justice in education may be realized? Even religion an movements which boast about abolishing discriminations have not been able to resolve this. Rather, they have ultimately adopted these divisive practices themselves.

Critics like Anil Sadgopal say that 25% reservation to poor children in private schools is more like a charity than bringing equality in education. It overlooks the cultural gap and disparity this will strengthen between the lower class non paying and upper class paying children. It demeans the initial demand for the neighborhood and common schooling system. It is also seen as a violation of Article 21A which is about free elementary education of equitable quality to the 6-14 year age group.

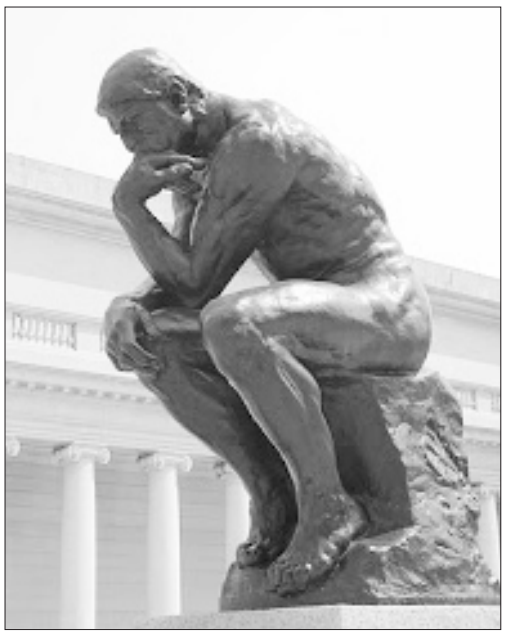

The struggle for RTE is not new in this country as it was started long back by Mahatma Jotirao Phule. Almost 125 years ago he raised his voice over British government catering only to the education of Brahmins and higher classes. In the later years the attempt to implement free and compulsory education bill was met with stiff resistance from ministers and feudal lords. After independence the biggest rhetoric used against the enactment of this bill has been the lack of resources.

RTE act was passed three years ago but the government never looked serious about its execution. At such a low percentage of GDP on education, the dream to fulfill even the quantifiable goals looks bleak. It should also be kept in mind that the implementation of RTE not only demands financial support and institutional change but needs revisiting the act itself. We should not forget that the ultimate goal of this act is to provide free and compulsory education to all in this country. One more aspect which is generally overlooked is the corresponding change in the mindset and attitude of the people of this country without which all other attempts look futile.

(Courtesy : The Companion)

ओरैया में मंडलीय सम्मेलन 20 अक्टूबर को

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के उत्तर प्रदेश के इकाई की ओर से **20 अक्टूबर, 2013** को ओरैया में मंडलीय सम्मेलन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण है। सम्मेलन में आस-पास के जनपद जैसे झांसी, जालौन, कानपूर, इटावा, इत्यादि जिले के भी कार्यकर्ता भाग लेंगे।

भवननाथ पासवान 09415158866
आर. के कमल 09759845668

All India Confederation of SC/ST Organisations - Karnatka unit is holding a conference in Bangalore on 6th October, 2013.Those who are the supporters of our movement, they are invited to participate.

Contact Person
Shri Nivasulu
09945597437

28 सितंबर को नवादा, बिहार में परिसंघ का सम्मेलन

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के बिहार प्रदेश इकाई की ओर से सम्मेलन का आयोजन 28 सितंबर को सुबह 10 बजे नवादा में किया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज होंगे। आप सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि सम्मेलन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं।

संपर्क
राजकुमार पासवान
09931434944

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Rest of Page-8...

National Convention on Education Policy

and change the world. What is the point in going to the moon if we can't understand our own world?

Vikas Gupta, AIFRTE: Our predication about RTE stands vindicated and this shows that our struggle is on the right path. We demand secular equitable education system from KG to PG, and such a system can only be public funded. There is a public rally on 21st October at Jantar Mantar. The fight for equal education is possible only by coming on a joint platform to fight against a common enemy. We need to include other marginalized also as minorities and disabled as marginalization is a multi causal phenomenon.

Professor Prem Singh, Hindi Department, DU: FYUP is anti-student. FYUP is fast becoming the most important issue in the DUSU elections. Today parents and students are ready to join the movement. Even the proponents of FYUP have realized that it was wrong. We need to consolidate all opposition against FYUP and attack it. The movement against fyup can replace the false struggles. We need to join hands in order to enhance the chances and expedite victory.

Sadashiv (Janwadi Sikshak Manch): The movement against FYUP has been successful in bringing together various forces. Lack of money will not a hindrance for the continuation of the movement. The fact that we were unable to stop FYUP has turned out to be good as it would not have lead to this kind of thinking on major policies on higher education.

Harish Khanna (SYS): There is no doubt that FYUP is against SC/ST/OBC. We will continue to fight against the policy changes. If the current reforms are not curbed, higher education will be accessible only to few. What we see is an attempt to destroy education. Students dropping out in large numbers from FYUP and opting for SOL and Non-Collegiate Women's Education Board. The new courses are at very low level. The high percentage of Internal Assessment can give rise to discrimination. Higher education is the right of everyone. There is a need for an action program inside the university. We should call out the students from the colleges. Education has to be need to use the forthcoming election to mobilize

Harsh Vardhan (SSYF): Mahatma Jyotiba Phule has realized that education right from the primary level is of utmost important. But recent reforms are destroying education. State universities are also seeing similar developments. There is a big movement against privatization of schools going on in Maharashtra. We need to have a common education system. All private schools have to be nationalized immediately. Baba Saheb Ambedkar was of the view that primary education should be the responsibility of the central government. What corporates like Reliance will do when they launch into education is nothing but create employees for his company by opening university and taking money from them.

Nandita Narain, DUTA President: The educational reforms unleashed by this government is actually a plan of selling out the Indian higher education sector to private players from India and abroad. It is the biggest exploitation since the days of East India Company. Such private players will transform the education sector in a way where the role of education towards social equity will be totally ignored in favour of a profit –driven structure. PPP is nothing but a way to put public money in private pockets . Since independence, Indians have not been subjected to a more discriminatory measure. Our fight against these reforms is a fight for protecting and upholding an education system committed to equity. We need to fight against a curriculum that is designed to kill the critical and thinking capacity of the students. Teachers have shown their fighting spirit by defeating the official candidate in the DUTA election.

Indu Choudhary (BHU, Secretary SC/ST Employees Union): Most of the issues that are discussed are not just a matter of Delhi University alone. VCs are autocratic everywhere. In Benares Hindu University, the situation is no better. There is no participation of SC/ST/OBC in decision making bodies like the Executive Council. We need to spread Ambedkar's views that has enabled the social quality in our country to such an extend as we see it today.

Sagar SK (FOCUS): There is a need for unity among SC, ST, and OBC. If that is achieved, there is no need of any support from other forces. We need to have reservation in private schools. We need to review the full pass system. In FYUP, 70% of SC/ST/OBC and poor will dropout after 2 years. Only elite will study full 4 years. FYUP is only for the elite. There are many issues that need to be fought against like the entry level screening based on point system in the .- sc/st/obc members in ac not supporting the causes for sc/st/obc

SECOND SESSION (3 pm onwards)

Alka: A lot of new universities have to be opened. Teachers have to be regularized by carrying out appointments. There is a need to improve primary education. We need for English for higher education. There are no books in Hindi in most subjects. Higher education should be in the same language as that of primary education, without which discrimination will be the result.

Tripta Wahi (Forum for Democratic Struggle): All issues like privatization, FYUP, and contractualization are inter-connected. The change of policies started in 1970s. 1986 saw the new education policy. In 1993 it was extended to higher education. Commercialization of education started from1991. We need to attack neo-liberalization.

DN Choudhary: There is a difference in education between India and Bharat. CBSE is for India, which is the elite. Ordinary schools belong to Bharat. The mid-day meal scheme is a conspiracy. And so is FYUP.

Captain Deepak Kumar (Pilot Air India): Lot of posts are getting dereserved in Haryana. The requirement of Haryana domicile is also creating problems for many who are in Delhi. Modern education is creating learned servants.

Munshi Ram: Privatization is the biggest disease.

Yogendra Yadav, Member, UGC: Instead playing the role of negating social inequalities, higher education today functions to consolidate social positions. We do not have any major scholarship for undergraduate programme. From 10th planning to 11th planning, there was an increase in the money available for education – but the opportunity was thrown in the well – a large portion of the money was not spent – even the money spent was used on buildings. We need to include the following in our demands: (i) a major scholarship programme for UG programme, (ii) there are 40 Central University and roughly 300 State Universities. Majority of students go to State University. Ruin has been imposed on State Universities. We need to demand restoration of State Universities and (iii) more colleges and hostels for Women. In a UGC meeting I had raised the following concerns on the FYUP at DU: (i) A university wishing to start a new course has to approach the UGC for its approval six months prior to starting the programme. Why this was not followed in the case of FYUP at DU? (ii) A switch to a four year programme from the existing three year programmes has infrastructural and logistical requirements. It has financial ramifications for the Government. Was this ever discussed before the implementation of FYUP? (iii) Has the FYUP been implemented under a National Policy. Which Committee /Commission proposed this format? The discussion on FYUP took more than an hour. The entire discussion was missing from the minutes. My objection to tampering of minutes became one of the reasons for the show cause notice issued by the MHRD.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 20 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 September, 2013

National Convention on Education Policy

From Left- Nandita Narayan, Dr. S. K. Sagar, Dr. Hany Babu, Dr. Udit Raj, Dr. Shaswati, Dr. Prem Singh, Bhavannath Paswan and Others

Hany Babu

Joint Action Front for Democratic Organization(SC/ST/OBC/Left) JAFDE organized a day long national convention at speaker hall, constitution club, New Delhi on 8th Sept, 2013. The convener , Dr Udit Raj , inaugurated it and at the outset he said that the education is the key factor to take forward any society but under the garb of globalization it is being thrown open to private players. The Right to Education was the hope for universalization of education but its fall outs are quite discouraging rather it is accelerating the privatization . The day is not far off when the higher education will be a distant dream for common people and SC/ST will be worst hit. Surprisingly the leaders of SC/ST/OBC are quite complacent on this burning issue . Commercialization of education is not in the interest of nation as a whole. India can become a super power in the world provided universal and equal education is introduced and an honest efforts are made to annihilate the caste system . The recent restructuring of the undergraduate program me at Delhi University with the introduction of the FYUP has brought into focus the policy changes advocated by the present government in withdrawing funding from education and back door entry for privatization . Though a fierce opposition was put up by various groups and organisations on issues of quality and access, the brazenness of the VC and the government in pushing through the changes suggest that this is part of the larger design towards private-sector led expansion in higher education. Simultaneously, an attempt is already afoot to dismember a public-funded university system by creating autonomous colleges, which will then be forced into private-public partnerships or corporate tie-ups, while students will be forced to obtain funding through education loans. The government has made clear its intention to withdraw from higher education. Privatization and corporatization of education have already been seen in school education and is already becoming rampant in higher education with the mushrooming of private enterprises. This will make quality education unaffordable and inaccessible to a vast majority of students and SC/ST/OBC will be affected the most. There is an urgent need to bring together all organizations and individuals throughout the country to create a national movement demanding equal education for all.

It is in this that JAFDE organized a One Day National Convention Against Privatization and Commercialization of Education on 8th September 2013, in the Speaker Hall, Constitution Club, New Delhi, with the aim to bring together the experiences of various groups and organizations fighting the government's withdrawal from funding of school and university education; to forge a united Nation-wide struggle to create awareness about the ramifications of these policy changes and to mobilize towards the demand for Equal Education. A large number of organizations and individuals participated in the programme. Given below is a gist of what some of the key speakers said:

Prof Shaswati Mazumdar, President, DTF: Education is the most potent means of social transform. Its special significance in the lives of historically marginalized sections cannot be undermined. The JAFDE is hence a social reform platform created in recognition of the need to make education more accessible to the marginalized at a time when the government is trying its best to make education exclusive and secure benefits for the privileged through privatization.

Dr. Dilip Behra of All-India confederation of SC-ST organization: Education must be universalized in spirit and practise in order to ensure that its meaning is realized. There is a deliberate attempt to throw out SC/ST and OBC from higher education. The need of the hour is to resist. We need to join hands and fight with along with Udit Raj.

Prof Hemlata Maheswar, Hindi Department, Jamia Millia Islamia: PPP model seeks to overturn the limited advancement and progress of the marginalized section after Independence. Delhi University's FYUP is also a perverse model of Higher Education which is designed to eliminate the presence of the marginalised sections – SCs, STs and OBCs -- from Higher Education. Reservation is a right. There is no representation of tribals even in the tribal universities. We need to evolve a pedagogy where we teach that "A" is for Ambedkar. We need to have an education that will enable us to understand

Rest on Page-7...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn